सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
मूल्य ₹ 3/-
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 9 ● अंक: 330 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, गुरूवार, 11 जनवरी, 2024

यदि आप एक कंपनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक केक बनाने की तरह है। आपको सभी सामग्री सही मात्र में डालनी होगी।

-इलोन मस्क

राशिद की पीठ की सर्जरी, रिहैबिलिटेशने... 7 | आसान नहीं है सीटों के बंटवारे को... 3 | बीजेपी की कारस्तानियों से सतर्क... 2

कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की नीतियों पर उठाए तीखे सवाल

गैर बीजेपी शासित राज्यों की गणतंत्र परेड की झांकी रोकने पर भड़के कर्नाटक के सीएम

» बेरोजगारी पर पीएम मोदी को घेरा, चार वर्षों में सबसे अधिक युवा परेशान

» कांग्रेस पार्टी बोली प्रतिशोध की राजनीति कर रही भाजपा सरकार

» बीजेपी ने भी कांग्रेस पर किया पलटवार

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। देश की दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस में विभिन्न मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर वार-पलटवार जारी है। जहां राममंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के शामिल होने से मना करने पर भाजपा आग बूबला हो गई है वहीं कांग्रेस ने कहा है देश में बेरोजगारी चरम पर है जबकि सरकार इधर-उधर के मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। इसबीच एक और गंभीर मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार की आलोचना की है। ये मामला 26 जवरी से संबंधित है। जिसमें केंद्र ने गैर बीजेपी शासित कई राज्यों की झांकी को नई दिल्ली के परेड में आने से रोक दिया है इसको लेकर भी सियासी घमासान दक्षिण से उत्तर भारत तक में मचा हुआ है।

कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति करने के आरोप लगाए। दरअसल इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में कर्नाटक की झांकी को शामिल नहीं किया गया है। इसे लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि केंद्र ने कर्नाटक की झांकी को इसलिए गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल नहीं किया है क्योंकि कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार है।

केंद्र ने सात करोड़ कन्नड़ लोगों का अपमान किया : सिद्धारमैया

सिद्धारमैया की पोस्ट पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह प्रतिशोध का मोदी मंत्र है। वह अभी तक मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार को भूले नहीं हैं। वह असल में एक छोटे व्यक्ति हैं। इस साल कर्नाटक की झांकी में मैसूर के राजा नलवाडी कृष्णराजा वडियार के साथ, रानी लक्ष्मीबाई की तरह अंग्रेजों से लड़ने वाली रानी चेनम्मा और बेंगलूरू के संस्थापक नादप्रभु केम्पगौड़ा के जीवन को प्रदर्शित करने का प्रस्ताव था। सीएम ने पोस्ट में लिखा कि केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की झांकी में कर्नाटक की झांकी को शामिल ना करके सात करोड़ कन्नड़ लोगों का अपमान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते साल भी कर्नाटक को ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था, जब केंद्र सरकार ने शुरुआत में कर्नाटक की झांकी को शामिल करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए झांकी को शामिल करने की मंजूरी दे दी थी। इस बार केंद्र सरकार ने फिर से कन्नड़ लोगों के अपमान का ट्रेंड जारी रखा है। कर्नाटक से झांकी के लिए कई प्रस्ताव भेजे गए थे लेकिन केंद्र सरकार ने सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया।

कांग्रेस अब बहिष्कार पार्टी : भाजपा

कांग्रेस आलाकमान की तरफ से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता ठुकराने पर भाजपा भड़क गई है। पार्टी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अब बहिष्कार पार्टी बन गई है। इन्होंने भगवान राम तक को काल्पनिक कहा था, जबकि महात्मा गांधी खुद राम-राज्य की कल्पना करते थे। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह कांग्रेस अब गांधी की नहीं नेहरु की बन कर रह गई है। इन्होंने कुछ समय पहले ही कांग्रेस के नेता रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भारत रत्न सम्मान समारोह तक का बहिष्कार किया था। भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा, कांग्रेस ने इससे पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और अब द्रौपदी मुर्मू जी के संसद में अभिभाषण का बहिष्कार किया। 2004 के बाद 2009 तक कांग्रेस ने कारगिल विजय दिवस का बहिष्कार किया। मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद 10 दिन तक कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया था। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। जब जीएसटी लागू हुआ तो उसका भी बहिष्कार किया। टी-20 के समय दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे, उसमें भी महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करके संतोष प्राप्त करने वाली प्रवृत्ति की परिचायक कांग्रेस के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है?

दस साल में रोजगार देने में विफल रहे पीएम मोदी : जयराम रमेश

कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि विगत 10 वर्षों में देश में नौकरियों के अकाल के हालात और भी बदतर हो गए हैं। कांग्रेस ने साथ ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर साल दो करोड़ रोजगार सृजन का अपना वादा पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत का युवा ऐसी तरक्की का हकदार है जो उसे अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरी दे, न कि 'बेरोजगारी और पकौड़े की दुकान।' उन्होंने कहा, 'सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी' के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में 25-29 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी 15.5 प्रतिशत रही जो लगभग चार वर्षों में सबसे अधिक है। उन्होंने आरोप लगाया, इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी की स्थिति अब कोविड-19 महामारी के समय से भी बदतर है। रमेश ने कहा कि 20-24 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर 45.5 प्रतिशत है। उन्होंने दावा किया कि 30-34 साल की उम्र वालों के लिए भी बेरोजगारी दर तीन साल के उच्चतम स्तर पर है। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में संकट विशेष रूप से भयावह है। अधिक से अधिक परिवार मनरेगा की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि कोई अन्य रोजगार उपलब्ध नहीं है। रमेश ने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री प्रति वर्ष दो करोड़ नौकरियां पैदा करने के अपने वादे को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र इस बार 31 जनवरी से प्रारंभ होकर 9 फरवरी तक चलेगा। सूत्रों के अनुसार इस दौरान 1 फरवरी को आम बजट भी पेश किया जाएगा। ये अंतरिम बजट होगा। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को 31 जनवरी को संबोधित करेंगी। बता दें कि 17वीं लोकसभा का यह अंतिम संसद सत्र भी होगा। इस बार का बजट आम चुनाव से ठीक पहले पेश किया जाना है। ऐसे में सूत्रों के अनुसार इस बार केंद्र सरकार की तरफ कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ था। उस दौरान संसद के दोनों सदनों के बीच कई अहम बिलों पर चर्चा हुई थी और कई अहम कानून भी पास कराए गए थे। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर भी विपक्ष केंद्र से जवाब मांग रहा था। विपक्षी दलों की मांग थी कि संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान में दें। जबकि केंद्र सरकार का कहना था कि विपक्ष सदन में अहम मुद्दों पर चर्चा करने से बच रहा है। शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदन से 140 से ज्यादा सांसदों को निलंबित भी किया गया था। दोनों ही सदन से सांसदों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निलंबित किया गया था। सांसदों के निलंबन को लेकर बाद में विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया था और संसद भवन से एक मार्च भी निकाला था।

1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री

बीजेपी की कारस्तानियों से सतर्क रहें : अखिलेश

» कहा- भाजपा के लिए जनता के मुद्दों का कोई मूल्य नहीं

» भाजपाई सपा के खिलाफ फैला रहे अफवाह

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को चेताया है कि वह बीजेपी की कारस्तानियों से सतर्क रहें। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा नकारात्मक राजनीति करने की आदी है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा के जाल में नहीं फंसना है। सभी 80 सीटों पर भाजपा को हराने के लिए एकजुट होना होगा। अखिलेश यादव प्रदेश सपा मुख्यालय पर सोशल मीडिया की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा का विकसित भारत का दावा झूठा है। भाजपा की 10 साल की सरकार में किसान की आमदनी दोगुनी नहीं हुई। बेरोजगारी भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है।

महंगाई से सभी त्रस्त हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। स्वास्थ्य सेवाएं जनसामान्य को उपलब्ध नहीं है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी पर करोड़ों लोगों का भरोसा है। समाजवादी पीडीए– पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सभी भाजपा सरकार के अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार हैं। समाजवादी पार्टी उनके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने एक्स के जरिये कहा है कि गठबंधन में बसपा को शामिल करने को लेकर सपा के खिलाफ बसपा, भाजपा और अन्य भाजपाई सहयोगी दलों की ओर से अफवाह फैलाई जा रही है। इसे कांग्रेस के कुछ नेता भी हवा दे रहे हैं। यह सपा के खिलाफ एक साजिश है।सपा अगर बसपा के खिलाफ होती तो 2019 में उसके साथ गठबंधन क्यों करती। बसपा ने वर्ष 2019 में कांग्रेस को गठबंधन में लेने से इंकार कर दिया था, जबकि सपा तब कांग्रेस, रालोद, बसपा और सपा का संयुक्त गठबंधन चाहती थी। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आगे कहा गया है कि सपा का एजेंडा एकदम स्पष्ट है कि भाजपा को हराना है और संविधान को बचाना है। इसके लिए कोई भी त्याग और कोई सख्त निर्णय लेना होगा तो लिया जाएगा।

अजमेर में उर्स के लिए अखिलेश यादव ने भेजी चादर

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दरबार ख्वाजा साहब में पेश करने के लिए चादर रवाना की। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 812वां सालाना उर्स अजमेर (राजस्थान) में 18 जनवरी को होगा। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश की प्रगति व खुशहाली और कौमी सद्भाव की कामना के साथ चादर हजरत पीर बरकत मियां हाशमी नियाजी मदारी कौमी सदर चिश्तिया कमेटी उत्तर प्रदेश को सौंपी। वे यह चादर सालाना उर्स के मौके पर पेश करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी, विधायक ओम प्रकाश सिंह, मुबीन खां मौजूद थे।

योगी सरकार के फैसले पर रोक लगाए केंद्र : जावेद

» यूपी मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत अतिरिक्त राज्यांश का भुगतान बंद करने के आदेश के बाद राज्य मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इस योजना को बहाल करने का अनुरोध किया ताकि मुसलमान विद्यार्थियों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर के नारे को सफल बनाया जा सके।

जावेद का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत अपना अंशदान बंद किये जाने के बाद राज्य सरकार ने भी इसी साल पांच जनवरी को एक आदेश जारी कर इस योजना के तहत पढ़ाने वाले शिक्षकों को मानदेय भुगतान के लिए अतिरिक्त राज्यांश पर रोक लगा दी गयी है। हालांकि प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने राज्यांश पर रोक लगाये जाने से इनकार करते हुए कहा है कि सरकार पिछले साल से अब तक के लंबित राज्यांश का भुगतान करेगी। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जावेद ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना से प्रदेश के लाखों मदरसा छात्र-छात्राओं को शिक्षा और समाज की मुख्यधारा से जोड़ा गया है जिनमें ज्यादातर पिछड़े वर्ग के हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2023 को एक आदेश में कहा कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 तक के लिए ही अनुमोदित है। इसी सिलसिले में राज्य सरकार ने इस साल पांच जनवरी को इस योजना के तहत अध्यापकों को दिए जाने वाले अतिरिक्त राज्यांश मानदेय पर रोक लगाने की कार्यवाही कर दी है।

मदरसा शिक्षकों के सामने जीविकोपार्जन की समस्या

इस सिलसिले में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे. रीभा ने राज्य के सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए है जिससे इस योजना के तहत नियुक्त मदरसा शिक्षकों के सामने जीविकोपार्जन की समस्या पैदा हो गई है। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया, 1995 में उत्तर प्रदेश में लागू हुई मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत इस वक्त प्रदेश के 7442 मदरसों में आधुनिक विषयों की शिक्षा देने वाले कुल 21216 शिक्षक अध्यापन कार्य कर रहे है. अतिरिक्त राज्यांश भी बंद होने से इन सभी का रोजगार पूरी तरह छिन गया है।

जल्द दिया जाएगा राज्यांश : दानिश

प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया, अभी तक यही व्यवस्था थी कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना में जब तक केंद्रांश दिया जाएगा तभी तक राज्यांश उपलब्ध कराया जाएगा। इस वजह से मदरसा शिक्षकों को भुगतान होने में देर हो रही थी लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ बैठक में यह तय किया गया कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत जो शिक्षक काम कर रहे हैं उन्हें राज्यांश दिया जाए। अंसारी ने कहा कि गत पांच जनवरी के पत्र में क्या लिखा है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ इस सिलसिले में हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही है और सरकार आधुनिकीकरण योजना के तहत तैनात शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा करेगी।

लाठी के बिना कोई काम नहीं होता : गोपाल मंडल

» जदयू से मांगी लोकसभा चुनाव की सीट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार में कई नेता इस बार लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी ठोंकते नजर आ रहे हैं। इन्हीं नेताओं में से एक हैं जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल। गोपाल मंडल अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। गोपाल मंडल ने फिर से एक बार ऐसा बयान दिया है जो कि सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोकते हुए कहा कि हम इस बार लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। हम क्लास वन कैंडिडेट हैं।

हम ऐसे ही थोड़े बोलते हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है। अब हम 14 तारीख से फिल्ड में उतरकर क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। हम घूमेंगे तब न वायरल होगा। अखबार में छपेगा तब न लोग जानेगा कि गोपाल मंडल क्या। अभी तो लोग कहते हैं गोपाल मंडल लाठी पटकता है। अरे लाठी नहीं पटकता है गोपाल मंडल। लाठी के बिना कोई काम ही नहीं होता है। लाठी पटकना पड़ता है।

मुख्यमंत्री सोचते हैं बदमाश हैं हम

गोपाल मंडल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरे मुख्यमंत्री सोचते हैं कि हम बदमाश हैं। अरे ऐसा नहीं है, हम तो सही आदमी हैं। कुर्सी मिलेगी तब न बताएंगे कौन हैं हम। उन्होंने कहा कि लाठी पटके बिना यहां कोई काम नहीं होने वाला है। गोपाल मंडल भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह अक्सर अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं। हाल ही में वह उस समय विवाद में आ गए थे जब वह रिवॉल्वर लेकर अस्पताल में घुस गए थे। इसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तो वह पत्रकार को ही धमकाने लगे। इससे पहले वह ट्रेन में चड्डी बनियान में घूमते नजर आए थे। जिसके बाद काफी विवाद हो गया था। लोगों ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी।

बामुलाहिजा
कार्टून: हसन जैदी

हर मुद्दे पर बातचीत के बाद ही कोई फैसला : अजय

» यूपी में 12 को फिर सीटों को लेकर सपा-कांग्रेस में चर्चा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि हर मुद्दे पर बातचीत हो रही है। 12 की बैठक के बाद सीटें तय होंगी। हालांकि वह सीटों की संख्या पर अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 35 से ज्यादा सीटों पर दावा कर रही है। पहले दौर की बातचीत में सीटों पर फैसला नहीं हो सका है। अब 12 जनवरी को दोबारा बैठक होगी। इसमें सीटों के मुद्दे पर फिर से चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को तीन श्रेणी में बांट कर ब्यौरा तैयार किया है।

पहली प्राथमिकता श्रेणी में 35 सीटें रखी हैं। जबकि दूसरी प्राथमिकता वाली 25 और तीसरी प्राथमिकता की 20 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर संभावित उम्मीदवारों, वोटबैंक की स्थिति, सियासी समीकरण आदि का ब्यौरा लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अविनाथ पांडेय सहित उत्तर प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में शीर्ष नेतृत्व के साथ भी सीटों पर मंथन हो चुका है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस ने पहली प्राथमिकता वाली सभी 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की मंशा जाहिर की है। कांग्रेस की ख्वाहिश है कि उसे पहली प्राथमिकता की सभी सीटें नहीं दी जाती है तो दूसरी प्राथमिकता वाली कुछ सीटें देकर भरपाई की जाए।

कांग्रेस ने 2009 में जीतीं थीं 21 सीटें

2009- कांग्रेस 69 सीटों पर चुनाव लड़ी और 21 जीती। इस चुनाव में सपा 75 पर लड़कर 23 और बसपा 69 पर लड़ी और 20 सीटें जीतीं।

2014- कांग्रेस 67 पर लड़कर सिर्फ दो सीट जीती। सपा 75 में पांच और बसपा 80 पर लड़ी और एक भी सीट नहीं जीत पाई।

2019- सपा- बसपा का गठबंधन था। कांग्रेस 67 पर लड़ी और सिर्फ रायबरेली जीत पाई। सपा 37 पर लड़ी और पांच जीती, जबकि बसपा 38 पर लड़ी और 10 जीती। रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद सपा के सिर्फ तीन सांसद हैं।

चुनावी चंदे में होता है खेल!

भाजपा का फंड अन्य सभी छोटी बड़ी पार्टियों को मिले चंदे का 70.69 प्रतिशत रहा

» एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा खर्च नहीं हुआ फंड

» बीजेपी ने जुटाया सबसे ज्यादा चंदा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। चुनावों के लिए सियासी पार्टियों द्वारा चंदा लेना आम बात है। सियासी दल जहां आम जन से छोटे-छोटे चंदे लेते हैं। वहीं कुछ बड़े उद्योगपति भी पार्टियों को फंड या चंदा देते हैं। ये चंदा करोड़ों रुपये में सियासी दलों को मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिन पार्टियां को करोड़ो में चंदा मिल रहा है क्या वह पार्टी चुनाव में इन पैसों को खर्च कर पाती है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। जिसमें बताया गया कि बीजेपी को पिछले साल यानी 2022-23 में इलेक्टोरल ट्रस्ट से 259.08 करोड़ का चंदा मिला।

हालांकि ये साल 2021-22 के चंदे से कम है लेकिन अन्य सभी छोटी बड़ी पार्टियों को मिले चंदे का यह 70.69 प्रतिशत है। साल 2021-22 में भारतीय जनता पार्टी को 336.50 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। एडीआर के इसी रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस को इलेक्टोरल ट्रस्ट से 17.40 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इतना ही चंदा आम आदमी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस को भी मिला है। रिपोर्ट कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी है भारतीय राष्ट्र समिति यानी वीआरएस. इस पार्टी को इलेक्टोरल ट्रस्ट से 90 करोड़ रुपये मिले है। अगर नहीं तो समझते है कि पार्टियां चंदा कितना और कैसे खर्च करती है? चुनावी खर्च को दो कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी इलेक्शन एक्सपेंसेस है, जिसे कानून के तहत चुनाव प्रचार के लिए अनुमति दी जाती है, बशर्ते वह तय की गई सीमा के भीतर हो। इसमें सार्वजनिक बैठकों, रैलियों के पोस्टर, बैनर, गाड़ियां, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन आदि जैसे प्रचार से जुड़ा खर्च शामिल होगा। चुनावी खर्च की दूसरी कैटेगरी में उन खर्चों को रखा जाता है जिसकी कानून के तहत अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए, मतदाताओं को अपने पाले में करने के इरादे से उन्हें धन, शराब या किसी अन्य वस्तु देना। चुनाव आचार संहिता के नियम 90 में साल 2022 में कुछ परिवर्तन किए गए थे, जिसके तहत निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यय को यानी चुनाव में होने वाले खर्च को लोकसभा और विधानसभा के लिए बढ़ा दिया था। चुनावी खर्च की ऊपरी सीमा हर राज्यों में अलग- अलग तय की गई है। इन राज्यों को छोटे और बड़े राज्यों में बांटा गया है और ये बंटवारा उनकी जनसंख्या के हिसाब से किया गया है। बड़े राज्यों में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों को शामिल किया गया है और छोटे राज्यों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सभी यूनियन टेरिटरी को रखा गया है।

लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा

बड़े राज्यों की खर्च सीमा- लोकसभा सीट के लिए चुनाव आयोग ने पर प्रत्याशी खर्च की सीमा 95 लाख तय की है। जिसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक कैंडिडेट पर कोई भी पार्टी 95 लाख तक खर्च कर सकती है। यह लिमिट साल 2022 से पहले 70 लाख थी जिसे साल 2014 में बढ़ाया गया था। 2014 से पहले इस खर्च की सीमा 40 लाख थी। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि केवल बड़े राज्यों की लिस्ट में शामिल कैंडिडेट ही लोकसभा चुनाव के दौरान 95 लाख खर्च कर सकते हैं। यानी छोटे राज्यों की कैटेगरी वाले तीन राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा इतना खर्च नहीं कर सकते हैं, छोटे राज्यों के खर्च की सीमा भी जान लीजिए- छोटे राज्यों और यूनियन टेरिटरी में लोकसभा चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार पर 75 लाख तक खर्च किया जा सकता है, ये सीमा साल 2022 से पहले 54 लाख थी और साल 2014 से पहले 22 लाख।

विधानसभा चुनाव में खर्च सीमा

बड़े राज्यों की खर्च सीमा-विधानसभा चुनाव के दौरान मैदान में उतरने वाले किसी भी उम्मीदवार पर पार्टी अधिकतम 40 लाख खर्च कर सकती है। यह सीमा साल 2022 से पहले 28 लाख थी और साल 2014 से पहले ये लिमिट केवल 16 लाख तक की थी। छोटे राज्यों का खर्च लिमिट- छोटे राज्यों की बात की जाए तो यहां साल 2022 में 20 लाख की सीमा को बढ़ाकर 28 लाख कर दी गई थी। वहीं साल 2014 से पहले ये लिमिट 14 लाख थी। बढ़ाई गई चुनावी खर्च की लिमिट दरअसल चुनावी खर्च की सीमा का अध्ययन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने साल 2020 में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने इसमें कॉस्ट फैक्टर और संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के बाद ये पाया कि साल 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स में पर्याप्त वृद्धि हुई है। चुनाव आयोग ने इसमें चुनाव प्रचार के बदलते तौर तरीकों को भी ध्यान में रखा जो कि अब फिजिकल के साथ धीरे धीरे वर्चुअल मोड में बदल रहा है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार साल 2014 से 2021 के बीच में 834 मिलियन से 936 मिलियन (12.23प्रतिशत) मतदाताओं की वृद्धि हुई है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में भी 2014-15 से 2021-22 में भी 32.08 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

पार्टियों पर चुनावी खर्चे पर कोई अंकुश नहीं

एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं- चुनाव में जो खर्चा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक उम्मीदवार पर कितना खर्च किया जा सकता है इसी सीमा तो तय की गई है। लेकिन, एक पार्टी कितना खर्च कर सकती है इसकी कोई लिमिट अब तक तय नहीं हुई है। अगर एक बार पार्टी के खर्चे की सीमा भी तय हो जाए तो पता लगाया जा सकता है कि किसी पार्टी को जितना चंदा मिल रहा है वह उसका कितना प्रतिशत खर्च कर पा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियों को हर दिन डीजल, गैसलीन, बैनर, होर्डिंग, प्रिस्क्रिप्शन और अन्य प्रमोशन मटेरियल पर खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा जुलूस या रैली निकाले जाने के लिए किराए पर गाड़ी लेने का खर्च, अखबार और टीवी पर प्रमोशनल विज्ञापन छपवाने और मार्केटिंग का खर्च भी इसी चंदे से पैसे से किया जाता है। इतना ही नहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के खाने पीने का खर्च भी इस फंड से पार्टी खर्च के रूप में जाता है। कुछ मामलों में तो लोगों को रैलियों में शामिल होने के लिए भी नकदी दी जाती है। अब तो फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के जरिए भी प्रचार शुरू हो गया है और पेड कैंपेनिंग भी चलाया जाता है।

कहां कितना होता है खर्च

चुनाव प्रचार में वाहनों पर खर्च कुल खर्च का 34 प्रतिशत होता है। अभियान सामग्री पर कुल खर्च का 23 प्रतिशत खर्च होता है। सार्वजनिक जनसभाओं पर खर्च होता है 13 प्रतिशत। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर खर्च होता है 7 प्रतिशत। बैनर, होर्डिंग और पर्चे पर खर्च होता है 4 प्रतिशत। चुनाव क्षेत्र भवन पर खर्च होता है 3 प्रतिशत होता है।

आसान नहीं है सीटों के बंटवारे का काम

» दिल्ली-पंजाब, महाराष्ट्र पर चर्चा

» कांग्रेस ने कहा- सबका लक्ष्य बीजेपी को हराना

» आप दे रही है कांग्रेस को टेंशन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से चर्चा को सार्थक बताया गया है और दावा किया क्या है कि आने वाले दिनों में फिर से बात की जाएगी। हालांकि, सूत्र बताते हैं कि बातचीत के दौरान लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कोई फार्मूला नहीं निकल सका है। आखिरकार इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की शुरुआत हो गई है। रविवार को जहां राजद और कांग्रेस की बैठक थी तो वहीं सोमवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई और दिल्ली तथा पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई।

कांग्रेस को कमजोर कर दिल्ली और पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनी आम आदमी पार्टी पर इस चर्चा के दौरान सबकी निगाहें थी। हालांकि, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से चर्चा को सार्थक बताया गया है और दावा किया क्या है कि आने वाले दिनों में फिर से बात की जाएगी। हालांकि, सूत्र बताते हैं कि बातचीत के दौरान लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर कोई फार्मूला नहीं निकल सका है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक में कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी के प्रमुख मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत समेत स्थानीय नेता भी शामिल हुए। वहीं, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और दिल्ली कैबिनेट की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने किया। दोनों ही ओर से बैठक के बाद मीडिया से कोई बातचीत नहीं की गई है। आप नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल ने एक दिन बाद बताया कि दोनों पार्टियों के नेताओं ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के समझौते पर बैठक की। आम आदमी पार्टी ने अपनी राय रखी है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा और गुजरात में उसकी मजबूत उपस्थिति है। इन राज्यों में हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, इस पर हम अगली बैठक में चर्चा करेंगे।

सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को तीन लोकसभा सीटें देने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली में लोकसभा के 7 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। कांग्रेस को 22 फीसदी तो आम आदमी पार्टी को 18 प्रतिशत वोट मिले थे। इसके अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 6 सीटों का ऑफर दिया है। पंजाब की कुल 13 सीटों में से 2019 में कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की टेंशन को बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की कुल 10 सीटों में से तीन पर दावा ठोक दिया।

फिर से चर्चा को मजबूर कांग्रेस

दिल्ली और पंजाब तो ठीक है लेकिन गुजरात, गोवा और हरियाणा में सीटें मांग कर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। यही कारण है कि कांग्रेस एक बार फिर से मंथन पर मजबूर हुई है। जब से आप इंडिया गठबंधन में शामिल हुई, तब से इस बात को लेकर दावा किया जा रहा था की दोनों पार्टियों में दिल्ली और पंजाब में सीट बंटवारे पर ही बात होगी। लेकिन गोवा और हरियाणा को लेकर आम आदमी पार्टी की डिमांड गठबंधन में पेंच फंसा सकती है। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो फार्मूला दिया है उसको कांग्रेस स्वीकार कर सकती है और उदारता दिखा सकती है। लेकिन हरियाणा, गुजरात और गोवा में कांग्रेस समझौते को लेकर तैयार नहीं होगी।

स्थानीय नेता गठबंधन के पक्ष में नहीं

दिल्ली और पंजाब की बात करें तो यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार आमने-सामने हैं। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को ही सत्ता से दूर कर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। यही कारण है कि दोनों पार्टियों के स्थानीय नेता किसी भी प्रकार के समझौते के पक्ष में नहीं है। स्थानीय नेताओं का मानना है कि भले ही ऊपर के नेताओं के हाथ मिल जाए लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिल सकते हैं। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने आलाकमान को कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। पंजाब कांग्रेस प्रमुख वडिंग ने कहा कि इस (सीट-बंटवारे) को लेकर मुझसे कोई चर्चा नहीं हुई है। हमें सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है और हम सभी पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर दोनों ही दलों में आने वाले समय में पेंच फंसेगा।

महाराष्ट्र में आगे बढ़ने का रास्ता ढूढेंगे : पवार

उधर महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर भी शरद पवार ने बात रखी। पवार ने कहा कि यह शुरुआती बैठक है और बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। जब कई पार्टियां एक साथ आती हैं तो आक्रामक मांगें की जाती हैं लेकिन सभी को मिलकर ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जो उस राज्य में काम करे जहां उनका प्रभुत्व नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को खारिज करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि एमवीए में सीटों का बंटवारा आसान होगा... सीटों का बंटवारा योग्यता के आधार पर किया जाएगा और एमवीए को सभी सीटों पर बीजेपी को हराना है, जिसके लिए पूरी योजना तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर भी अपनी बात रखी। पवार ने कहा कि यह शुरुआती बैठक है और आज की बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। जब कई पार्टियां एक साथ आती हैं तो आक्रामक मांगें की जाती हैं लेकिन सभी को मिलकर ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जो उस राज्य में काम करे जहां उनका प्रभुत्व नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को खारिज करने की कोशिश कर रही है।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डर गई भाजपा!

लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस एक बार फिर यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा की अगुवाई एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ही करेंगे। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली कांग्रेस की यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 राज्यों से होकर 6700 किमी की दूरी तय करते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। यह यात्रा 110 जिलों, 100 लोकसभा सीटों और 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव को साधने का प्रयास करेगी। लेकिन इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही भाजपा की बेचैनी देखी जा सकती है। तभी भाजपा ने यात्रा शुरू होने से पहले ही उसमें रोड़े अटकाने शुरू कर दिए हैं। मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले के हट्टा कांगजेइबुंग से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए मणिपुर की भाजपा सरकार ने अनुमति देने से इंकार कर दिया है। जिसके बाद अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। साथ ही कांग्रेस ने इसके वैकल्पिक स्थान को भी तलाशना शुरू कर दिया है।

कांग्रेस का कहना है कि हम यात्रा मणिपुर से ही शुरू करेंगे। इस बीच अब सवाल ये ही उठ रहा है कि क्या वाकई में भाजपा राहुल गांधी की इस यात्रा से इतना घबरा गई है कि यात्रा में अभी से ही अड़ंगे लगाने लगी है। क्योंकि जाहिर है कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस एक बार फिर आम जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगी। राहुल एक बार फिर लोगों के बीच में जाएंगे, आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के इस प्लान से भाजपा के खेमे में खलबली साफ तौर पर देखी जा सकती है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भाजपा सरकार की ओर से राहुल गांधी को मणिपुर जाने से रोकने का प्रयास किया गया हो। इससे पहले जब हिंसा के समय राहुल गांधी मणिपुर गए थे और वहां पीड़ितों से मिलना चाह रहे थे, तब भी मणिपुर सरकार ने उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी थी और उनको रास्ते में ही रोक दिया था। हालांकि, राहुल बाद में हेलीकॉप्टर के द्वारा पीड़ितों के शिविरों तक पहुंचे थे। अब एक बार फिर राहुल गांधी के मणिपुर पहुंचने में भाजपा ने अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया है। मणिपुर पिछले कई महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी एक भी बार वहां झांकने तक नहीं गए। राहुल हिंसा के वक्त भी मणिपुर पहुंचे थे और अब एक बार फिर वो अपनी यात्रा की शुरूआत भी मणिपुर से ही करने जा रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा परेशान है और किसी भी तरह से राहुल को मणिपुर जाने से रोकना चाह रही है। लेकिन राहुन न तब रुके थे और न ही वो इस बार रुकने वाले हैं। लेकिन राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भाजपा का डर साफ दिख रहा है।

मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले के हट्टा कांगजेइबुंग से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए मणिपुर की भाजपा सरकार ने अनुमति देने से इंकार कर दिया है। जिसके बाद अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। साथ ही कांग्रेस ने इसके वैकल्पिक स्थान को भी तलाशना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि हम यात्रा मणिपुर से ही शुरू करेंगे। इस बीच अब सवाल ये ही उठ रहा है कि क्या वाकई में भाजपा राहुल गांधी की इस यात्रा से इतना घबरा गई है कि यात्रा में अभी से ही अड़ंगे लगाने लगी है।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

यादों की कसक में मंदिर बतौर एक जीत

राजेश रामचंद्रन

जनवरी की एक बर्फीली सुबह को पड़ोस की श्रमिक कालोनी से आते ऊंचे नारों से नींद टूटी। नारे थे 'जय श्री राम' के और एक छोटा झुंड घर-घर जाकर अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लला की मूर्ति के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के बारे में सूचना दे रहा था। मैंने खुद को अन-आमंत्रित महसूस किया। क्या यह इसलिए कि मुझको भी वे मैकालेपुत्र मानकर या सटीकता से कहें तो चर्चिलपुत्र की तरह ले रहे हैं, जिसे किसी भी भारतीय चीज या हिंदू शब्द से चिढ़ थी या फिर मैं उनके आक्रामक हिंदू राष्ट्रवाद का साथ न देने वाला एक गांधीवादी अमनपसंद व्यक्ति हूं। खैर, मैकालेपुत्र, गांधीवादी राष्ट्रवादी और हिंदू पुनर्जागरण कर्ता- सरल या प्राय: गाली जैसी शब्दावली में- ये तीनों मौजूदा भारतीय राजनीतिक चलन में प्रतिस्पर्धात्मक धाराएं हैं, जिसमें तीसरी किस्म ने अन्यों को पछाड़ दिया है।

अयोध्या में राम मंदिर का बनना हिंदू पुनरुत्थानवादियों के लिए जीत का प्रतीक है। एक पूर्व ब्रिटिश औपनिवेशिक कालोनी में राष्ट्रवाद भारत की मुख्य राजनीतिक भावना बना रहा और यह जातीय, क्षेत्रीय और भाषाई भेदों पर भारी पड़ता है। हिंदू पुनरुत्थानावादियों की जीत के पीछे खुद को भारतीय राष्ट्रवाद का एकमात्र ध्वजवाहक होने की दावेदारी की सफलता है, जिसे उन्होंने आसानी से धार्मिक-राजनीतिक परियोजना में तब्दील कर डाला और यहां पर राजनीतिक चलन की अन्य दो धाराएं पस्त हो गईं। पहली हार हुई गांधीवादी राष्ट्रवादियों की। जब तक इसका जोर रहा, हिंदू दक्षिणपंथी पुनरुत्थानवादी मुख्यधारा का राजनीतिक दल नहीं बन पाए। वास्तव में, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो इसने गांधीवादी समाजवाद को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बताया था, जो भारतीय राष्ट्रवाद के इस शाश्वत प्रतीक को भुनाने का प्रयास था।

सलमान रश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस पर प्रतिबंध, शाह बानो मामले में अदालती फैसले को उलटना और जिन्ना की मुस्लिम लीग से पुराना गठबंधन कायम रखने वाले दोहरे चरित्र ने साम्प्रदायिक आधार पर राजनीति करके वाले सत्ता हथियाने के आरोपों को वैधता दे डाली। यदि इस्लाम का इस्तेमाल वोट पाने के लिए हो सकता है तो फिर हिंदुत्व क्यों नहीं? बदतर इसी बीच, कांग्रेस में गांधीवादी राष्ट्रवाद के उत्तराधिकारियों ने इस विचार को हिंदू-मुस्लिम एकता और सौहार्द में तब्दील करते हुए प्रतिगामी इस्लामिक मौलानाओं का तुष्टिकरण करके, जिन्हें धार्मिक आधार पर अलगाववाद तक से गुरेज नहीं था, अपने मूल सिद्धांतों का मखौल बना डाला।

भूमिका रही नव-भारत के वामपंथी छद्म-बुद्धिजीवियों की, जिन्होंने पूर्व-आधुनिक युगीन इस्लामिक प्रतिगामिता को न्यायोचित सिद्ध करने में सारा जोर लगा दिया। भारतीय वामपंथ, जो खुद को उत्तर-आधुनिक युगीन लोकतंत्र की आवाज होने का दावा करता है, वह इस्लामिक धार्मिक अलगाववादियों और कश्मीर घाटी से हिंदुओं के धार्मिक आधार पर सफाए को न्यायोचित बताने का हर संभव प्रयास करता रहा। द्वि-राष्ट्र का सिद्धांत मैकाले की खोज न होकर चर्चिल की सनक अधिक था। तथापि, उत्तर-आधुनिक युगीन शिक्षाविद, लेखक और राजनेता खुद को ऐसा समूह बताते रहे जिसे ऐसे भारत की परिकल्पना स्वीकार्य नहीं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहें। जब पश्चिमी साहित्य पुरस्कार विजेता और पश्चिम-अनुमोदित शिक्षाविद साम्प्रदायिक अलगाववाद के शिकार बने लोगों की दयनीयता को नजरअंदाज करने लगे या धार्मिक आधार पर देश के टुकड़े करने की बात करने वालों की बैठकों में भाग लेने लगे, और जब औपनिवेशिक शासकों की तरह उनका द्वि-राष्ट्रीय एजेंडा और प्रत्यक्ष होने लगा, तब उन्हें मैकालेपुत्र कहकर पुकारा जाने लगा।

आगे, इस प्रक्रिया में, भारतीय वामपंथ ने राष्ट्रवाद को अंधराष्ट्र की दुकान ठहराकर आलोचना करनी शुरू कर दी। इसने मजबूत मध्यमार्गी दल (कांग्रेस) का तोड़ करने को बेशर्मी से जातीयता और भाषाई आधार पर अलगाववाद को हथियार बनाया। इंदिरा गांधी जैसा नेता, जो पश्चिम-प्राधान्यता को चुनौती देने की कूवत रखता हो, कहीं ऐसा कोई और नेता न उभर आए, यह डर नव भारतीय वामपंथ में तारी रहा, जिसमें ज्यादातर गिनती पश्चिमी शिक्षाप्राप्त या पश्चिमी सोच से ओतप्रोत शिक्षाविदों, लेखकों और पत्रकारों की है। एक राष्ट्रीय पत्रिका के पहले संस्करण में दावा किया गया कि 70 फीसदी कश्मीरी भारत से अलग होना चाहते हैं, हालांकि किस सर्वे को आधार बनाया यह आज तक रहस्य है। यह 1990 के दशक की उथल-पुथल थी, जब दक्षिणपंथी हिंदुत्व इस नव-वामपंथ और पुरानी कांग्रेस के गांधीवादी राष्ट्रवाद के वारिस झंडाबरदारों से मुकाबले को बतौर एक मान्य ताकत बनकर उभरने लगा।

आधुनिक तकनीक से समृद्ध हो शैक्षिक पाठ्यक्रम

यह देश जहां पर पिछड़े हुए इलाके हैं, पहाड़ों में बिखरी हुई जनसंख्या है और हमारा ग्रामीण समाज है जिन्हें शिक्षा के नाम पर पुरातनपंथी अध्यापकों द्वारा पुराने सिलेबस की वही रिवायती शिक्षा परोसी जाती है। लेकिन दूसरी ओर शुरू हो गई देश में कौशल विकास योजना। इस बदले हुए युग में युवाओं को इंडस्ट्री के नये युग के अनुरूप ढालना पड़ेगा। कृत्रिम मेधा आ गई, 3डी प्रिंटिंग आ गई, रोबोटिक्स आ गई और डीपफेक जैसा कुप्रचलन आ गया।

सुरेश सेठ

हमने 2024 में कदम रख लिया है। यह कदम है नये ज्ञान का, इंटरनेट ताकत का, चैट जीपीटी का और कृत्रिम मेधा का। रोबोटिक्स युग शुरू हो गया। इस युग के आविर्भाव के लिए हमें पहले तो देश की वास्तविकता की पहचान करनी होगी। यह देश जहां पर पिछड़े हुए इलाके हैं, पहाड़ों में बिखरी हुई जनसंख्या है और हमारा ग्रामीण समाज है जिन्हें शिक्षा के नाम पर पुरातनपंथी अध्यापकों द्वारा पुराने सिलेबस की वही रिवायती शिक्षा परोसी जाती है। लेकिन दूसरी ओर शुरू हो गई देश में कौशल विकास योजना। इस बदले हुए युग में युवाओं को इंडस्ट्री के नये युग के अनुरूप ढालना पड़ेगा। कृत्रिम मेधा आ गई, 3डी प्रिंटिंग आ गई, रोबोटिक्स आ गई और डीपफेक जैसा कुप्रचलन आ गया। इस साल की अंतिम मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अन्वेषण, नयी सोच, शोध और नये अध्यवसाय की बात की है लेकिन उसके लिए चाहिए अधिक निवेश।

नीति आयोग का कहना है कि देश की सकल घरेलू आय का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा विकास पर खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन इस समय तक भी शिक्षा विकास पर हम केवल 2.9 प्रतिशत ही खर्च कर रहे हैं। कहा गया है कि इस बार अर्थात 2023-24 में हमने शिक्षा विकास पर 1.12 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2019-20 में भी हमने 94 हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया था। जरूरत है इस समय शिक्षकों को नई डिजिटल शिक्षा के आधार पर प्रशिक्षित किया जाए। चाहे देश में 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें 38 हजार शिक्षकों को नियुक्ति मिलेगी ताकि शुरू से ही ये शिक्षक जमीनी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को बदलें और बेहतर बनाएं। शिक्षक इंग्लैंड, अमेरिका और सिंगापुर में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाएं। सिंगापुर शिक्षा के बेहतरीन मॉडल के तौर पर जाना जाता है। इसीलिए पंजाब सरकार ने शिक्षकों के ग्रुप सिंगापुर में भेजे हैं लेकिन समग्र शिक्षा अभियान में सबसे पहले तो शिक्षकों का चयन करने के लिए उनकी सीमा रेखाओं को बड़ा किया जाए और उससे पहले शिक्षकों की कमी तो पूरी की जाए।

प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक तमाम पद खाली पड़े हैं। कच्चे और अस्थाई अध्यापक काम चला रहे हैं। शिक्षा युग को बदलना है और उससे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनानी है तो यह अस्थाई अध्यापकों की नींव पर नहीं बनेगी। देश में ग्रामीणों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए एकल अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए एकल शिक्षा ऑन व्हील बसें देश के 20 से अधिक राज्यों में गांव-गांव घूमकर लोगों को कंप्यूटर से परिचित करवा रही हैं। नया युग है, इसमें बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी कंप्यूटर प्रशिक्षण हासिल करने के साथ-साथ निपुण भी होना चाहते हैं। लेकिन क्या जो एकल शिक्षा ऑन व्हील का अभियान शुरू हुआ है, वह काफी होगा? अनुमान है कि इस गाड़ी पर प्रति वर्ष 12 लाख रुपये खर्च होते हैं। इसमें 9 लैपटॉप रहते हैं। एक बार में 18 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वाहन में सौर ऊर्जा से चलने वाले जेनरेटर की भी व्यवस्था है। यहां सर्च इंजन तक का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। चाहे अभी यह योजना झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक राज्यों में चल रही है लेकिन योजना बने कि देश के कोनों में भी ऐसे पक्के डिजिटल शिक्षा केन्द्र स्थापित किए जाएं जो लोगों को डिजिटल साक्षर कर सकें। इस साल 42 हजार लोगों को डिजिटल साक्षर करने का लक्ष्य है। दरअसल, 42 हजार से 42 लाख तक जाने की यात्रा सबके सहयोग से ही पूरी हो सकती है। सरकार ने अपनी ओर से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तो स्थापित कर दी है, जिससे देश के हर उम्र के लोगों को पढ़ने के लिए किताबें और दूसरी सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन इस डिजिटल लाइब्रेरी को भरने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के शोध प्रभागों, नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट को भी ज्ञान बांटने के डिजिटल युग में प्रवेश करने के लिये पर्याप्त तैयारी करनी पड़ेगी।

देश में प्रधानमंत्री की इस वर्ष 14,500 पी.एम. श्रीस्कूल स्थापित करने की योजना है, जिस पर अगले पांच सालों में 27,360 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे 20 लाख से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन 5 साल के इस अंतराल में जो प्रतीक्षा डिजिटल होने में लोगों को करनी पड़ेगी, उसके लिए अति आवश्यक है कि तत्काल इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए शिक्षा के वर्तमान ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन हो। अर्थात पालिटेक्निक से लेकर इंजीनियरिंग तक और आयुर्वेद से लेकर मेडिकल शिक्षा तक कृत्रिम मेधा का वह सहारा दिया जाए कि जिसके बगैर अभी इनके सिलेबस पूरे आधुनिक ज्ञान से पिछड़ रहे हैं। डिजिटल आधारित अर्थव्यवस्था बनानी है तो उसे बनाने की दृष्टि से लेकर कारगुजारी, पुस्तकों और सिलेबस तक सब बदलना पड़ेगा।

इन सामानों के बगैर अधूरा है लोहड़ी का त्यौहार

लोहड़ी का महत्व

लोहड़ी का पर्व देशभर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व फसल की कटाई और नई फसल के बोने से लेकर संबंधित है। इस दिन देवताओं को शुक्रिया के तौर पर रबी की फसल के रूप में आग में रेवड़ी, तिल, मूंगफली, गुड़ आदि अर्पित करते हैं। इसके साथ ही अग्नि देव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी फसल हमेशा अच्छी उत्पन्न हो। पंजाबी लोक कथाओं के अनुसार लोहड़ी पर जलाए गए अलाव की लपटें लोगों के संदेश और प्रार्थनाओं को सूर्य देवता तक ले जाती हैं ताकि ग्रह पर गर्मी आए ताकि फसलों को बढ़ने में मदद मिल सके। बदले में सूर्य देव भूमि को आशीर्वाद देते हैं और ठंड के मौसम को समाप्त करते हैं। लोहड़ी के अगले दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है।

कब है लोहड़ी

बता दें कि लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस साल सूर्य मकर राशि में 15 जनवरी को 2 बजकर 32 मिनट पर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में मकर सक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा और लोहड़ी का पर्व 14 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा।

भारत एक ऐसा देश है, जहां हम हर धर्म और समुदाय के विभिन्न त्योहार मनाते हैं। चाहे होली, दिवाली हो या फिर ईद का पर्व हो, हर त्यौहार को लोग मिलजुल कर सेलिब्रेट करते हैं। अब जब कुछ ही दिनों में लोहड़ी का त्यौहार आने वाला है तो उसकी धूम भी बाजारों में दिखाई देने लगी है। दरअसल, लोहड़ी का त्यौहार वैसे तो मुख्य रूप से पंजाब में मनाया जाता है, लेकिन अन्य राज्यों में भी इसकी धूम दिखाई देती है। लोहड़ी के दिन लोग पारंपरिक तरीके से तैयार होते हैं। जिस तरह से बिना खाने के हर त्यौहार अधूरा होता है, ठीक उसी तरह से इस त्यौहार में खाने का भी काफी महत्व होता है। अगर आप भी इस लोहड़ी के त्यौहार पर अपने घर मेहमानों को बुला रहीं हैं, तो उनके लिए पहले से ही कुछ पारंपरिक डिश तैयार कर सकती हैं। दरअसल, कुछ खाने के सामान ऐसे हैं, जिनके बिना लोहड़ी का त्यौहार अधूरा सा लगेगा।

तिल के लड्डू

सर्दियों के मौसम में तिल खाने का रिवाज होता है। ऐसे में कोशिश करें कि पहले से ही त्योहार के लिए तिल के लड्डू तैयार करके रख लें। ताकि त्यौहार वाले दिन आपको ज्यादा काम ना करना पड़े।

मूंगफली

भूनी हुई गर्म मूंगफली खाने का सर्दी में अलग ही मजा होता है। ऐसे में मूंगफली को अपने परिवार के लिए पहले से तैयार करके रख लें, ताकि आप सर्दियों में इसका आनंद ले सकें।

रेवड़ी

सर्दी के मौसम में आपको लगभग सभी बाजारों में आसानी से तिल और चीनी या गुड़ से बनी रेवड़ी मिल जाएगी। ऐसे में लोहड़ी का त्यौहार रेवड़ी के बिना भी अधूरा रहता है। लोहड़ी के दिन जब अग्निदेव के चक्कर लगाए जाते हैं, तब उस आग में रेवड़ी भी चढ़ाई जाती है।

गुड़ का हलवा

अगर कुछ स्वादिष्ट और ऐसा बनाने का सोच रहे हैं, जो हेल्दी भी हो तो आप गुड़ का हलवा तैयार कर सकते हैं। सर्दियों में गुड़ खाने से शरीर को काफी फायदा मिलता है। ऐसे में लोहड़ी के दिन घी, सूजी, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स से बना यह हलवा एक परफेक्ट डेजर्ट साबित होगा।

गजक

लोहड़ी का त्यौहार गुड़, गजक के साथ मनाया जाता है। इन मिठाइयों के बिना लोहड़ी का असली स्वाद नहीं आता। ऐसे में पहले से ही त्यौहार के लिए गजक तैयार करके रखें।

हंसना मना है

बुढ़िया (डॉक्टर से)-दांत निकाल दीजिए। डॉक्टर-मुंह खोलो। बुढ़िया-लो खोल दिया। डॉक्टर-थोड़ा और खोलो। बुढ़िया ने छोटा मुंह और खोल दिया। डॉक्टर-थोड़ा और खोलो। बुढ़िया ने सारा मुंह ऊपर किया। डॉक्टर-थोड़ा और खोलो। बुढ़िया (क्रोध में)-क्या मुंह में बैठकर ही दांत निकालने का विचार है?

एक पार्टी में एक सज्जन ने नजदीक खड़े इंसान से कहा-औरत भी अजीब वस्तु है। कुछ देर पहले तक वह सामने वाली स्त्री मुझे देख मुस्करा रही थी एवं अब ऐसे घूर रही है, जैसे कच्चा ही चबा जाएगी। जी हां, मेरी पत्नी का मूड इसी तरह बदलता रहता है। नजदीक खड़े इंसान ने उत्तर दिया।

संजय-हाल ही में पैदा हुआ तुम्हारा भाई इतना रोता क्यों है?अजय-बात ये है कि यदि तुम्हारे एक भी दांत न हो, सिर गंजा हो, पैर इतने दुर्बल हों कि आप खड़े भी न हो सको। ऐसी हालत में मेरा ख्याल है कि तुम्हें भी रोना आएगा।

बैंक मैनेजर-तो आखिर आपने बीवी को तलाक दे दिया। अकाउन्ट होल्डर-आपको कैसे पता चला? मैनेजर-आपके अकाउंट में रकम बढ़ती जा रही है।

कहानी | हाथी और शेर

एक बार एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मेरे पास तो तेज धारदार मजबूत पंजे और दांत हैं। साथ ही मैं एक बहुत ही ताकतवर जानवर भी हूं, लेकिन फिर भी जंगल के सारे जानवर हमेशा मोर की ही तारीफ क्यों करते रहते हैं। दरअसल, शेर को इस बात से बहुत जलन महसूस होती थी कि सभी जानवर मोर की तारीफ करते थे। जंगल के सभी जानवर कहते थे कि मोर जब भी अपने पंख फैलाकर नाचता है, तो वह बहुत सुंदर लगता है। यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि इतना ताकतवर होने और जंगल का राजा होने पर भी कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। ऐसे में उसके इस जीवन का क्या मतलब है। तभी वहां से एक हाथी जा रहा था। वह भी काफी दुखी था। जब शेर ने उस दुखी हाथी को देखा, तो उससे पूछा - तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है और तुम ताकतवर भी हो। फिर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या परेशानी है? दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा कि क्यों न मैं इस हाथी के साथ अपना दुख बांट लूं। उसने आगे कहते हुए हाथी से पूछा - कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है, जिससे तुम्हें जलन होती हो और वह तुम्हें हानि पहुंचाता हो? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा - जंगल का सबसे छोटा जानवर भी मुझ जैसे बड़े जानवर को परेशान कर सकता है। शेर ने पूछा - वह कौन सा छोटा जानवर है? हाथी ने कहा - महाराज, वो जानवर चींटी है। वह इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब भी वो मेरे कान में घुसती है, तो मैं दर्द के मारे पागल हो जाता हूं। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ में आ गया कि मोर तो मुझे चींटी की तरह परेशान भी नहीं करता है, फिर भी मुझे उससे जलन होती है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग-अलग खामियां और खूबियां दी हैं। इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ही ताकतवर या कमजोर नहीं हो सकते हैं। इस तरह शेर को यह समझ में आ गया कि उस जैसे ताकतवर जानवर में भी खूबियों के साथ कमियां हो सकती है। इससे शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और उसने मोर से जलन करना बंद कर दिया।

7 अंतर खोजें

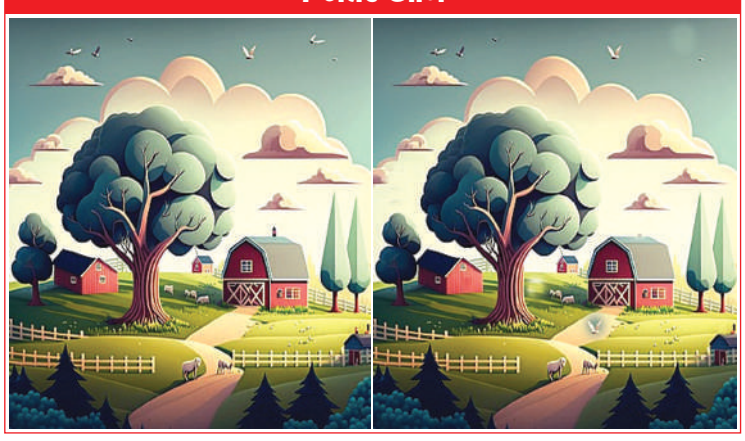

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

पुराने किए गए प्रयासों का लाभ मिलना प्रारंभ होगा। मित्रों की सहायता कर पाएंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें।

वृषभ

पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। अनहोनी की आशंका रहेगी। शत्रुभय रहेगा। कानूनी अड़चन दूर होगी। जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार में वृद्धि होगी।

मिथुन

प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि होगी। जीवनसाथी से अनबन हो सकती है। स्थायी संपत्ति खरीदने-बेचने की योजना बन सकती है। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी।

कर्क

पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है। अज्ञात भय सताएगा। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। कुसंगति से बचें।

सिंह

पारिवारिक समस्याओं में इजाफा होगा। चिंता तथा तनाव बने रहेंगे। भागदौड़ रहेगी। दूर से बुरी खबर मिल सकती है। विवाद को बढ़ावा न दें। बनते कामों में बाधा हो सकती है।

कन्या

वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। जरा सी लापरवाही से अधिक हानि हो सकती है। पुराना रोग बाधा का कारण बन सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें।

तुला

दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। सुख के साधन जुटेंगे। पराक्रम बढ़ेगा। घर में मेहमानों का आगमन होगा।

वृश्चिक

पूजा-पाठ में मन लगेगा। कोर्ट व कचहरी के काम बनेंगे। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। व्यापार लाभदायक रहेगा। नौकरी में चैन रहेगा। निवेश शुभ रहेगा।

धनु

नई योजना बनेगी जिसका लाभ तुरंत नहीं मिलेगा। सामाजिक कार्य करने में रुचि रहेगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शारीरिक कष्ट संभव है। चिंता तथा तनाव हावी रहेंगे।

मकर

कोई बड़ी बाधा आ सकती है। राजभय रहेगा। जल्दबाजी से काम बिगड़ेंगे। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

कुम्भ

यात्रा में सावधानी रखें। जल्दबाजी से हानि होगी। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। चिंता तथा तनाव रहेंगे। पुराना रोग उभर सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें।

मीन

शारीरिक कष्ट से बाधा संभव है। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। आय में वृद्धि होगी।

बॉलीवुड | मन की बात

कपड़े न होने का बहाना बनाकर अॅवार्ड शो में नहीं पहुंचते हैं विजय

साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति इन दिनों अपनी आगामी फिल्म मैरी क्रिसमस को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म में उनके के साथ कैटरीना कैफ नजर आने वाली हैं। विजय लगातार फिल्म की प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। प्रमोशन के दौरान एक्टर ने अवॉर्ड शोज में न जाने के कारण खुलासा किया है। अपनी दमदार एक्टिंग से विजय ने लाखों को दिलों को जीता है और कई अवॉर्ड्स भी जीते हैं। मगर एक्टर को लेकर एक बात नोटिस की जाती है कि वो अवॉर्ड शोज में कम ही शामिल होते हैं। जब एक बार उन्हें अवॉर्ड शो में इनवाइट किया गया था लेकिन उन्होंने शो में ना जाने के लिए ऐसा बहाना दिया, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। मीडिया के साथ बातचीत में विजय सेतुपति ने बताया कि कैसे उन्होंने एक अवॉर्ड शो के इनविटेशन आया था और उन्होंने उन्हें एक मजेदार बहाना मारकर मना कर दिया था। उन्होंने कहा, मैडम मैं नहीं आ सकता। मेरे पास कपड़े नहीं है। इस बीच कैटरीना ने कहा कि किसी भी इनविटेशन को मना करने का ये बहुत सभ्य तरीका था। इसके साथ ही विजय सेतुपति ने ये भी खुलासा किया कि वह किसी भी एक्टर के फैन नहीं है। हालांकि, उन्होंने इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा, मैं किसी का फैन नहीं हूं क्योंकि अगर हो गया तो आप सिर्फ उस एक्टर के काम को देखोगे जो कि किसी भी एक्टर के लिए ठीक नहीं है। मैरी क्रिसमस में कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म हिंदी और तमिल दोनों वर्जन में रिलीज होगी। फिल्म में राधिका आप्टे और अश्विनी कालसेकर का कैमियो भी देखने को मिल सकता है। श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित और रमेश तौरानी, संजय राउत्रे, जया तौरानी और केवल गर्ग द्वारा निर्मित फिल्म मैरी क्रिसमस 12 जनवरी, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

12th फेल की सक्सेस से मेधा शंकर के फॉलोवर्स की आयी बाढ़

विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 12th फेल थिएटर्स में जबरदस्त हिट साबित हुई है। फिल्म की कहानी दर्शकों के दिलों को जीतने में कामयाब हुई है। विक्रांत मैसी के स्ट्रगल से लेकर मेधा शंकर का सच्चा सपोर्ट देखकर फैंस काफी खुश हुए हैं। फिल्म की सक्सेस के साथ एक्ट्रेस भी रातों रात फेमस हो गई हैं।

फिल्म 12th Fail के ओटीटी पर रिलीज होने के बाद से मेधा शंकर का नाम हर तरफ छा रहा है। इस फिल्म में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर एक्ट्रेस ने हर किसी को प्रभावित किया है। इतनी ही नहीं मेधा शंकर की खूबसूरती ने भी फैंस के दिलों को जीता है। फिल्म 12th Fail के ओटीटी पर रिलीज होने के बाद से मेधा शंकर का नाम हर तरफ छा रहा है। इतनी ही नहीं मेधा शंकर की खूबसूरती ने भी फैंस के दिलों जीता है।

लेकिन ओटीटी पर फैंस की तरफ से मिले पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते मेधा शंकर के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या में बीते एक हफ्ते में एक मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स की बढ़ोत्तरी हुई है। जिसके चलते अब इंस्टाग्राम पर मेधा के चाहने वालों की टोटल संख्या करीब 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गई है। 29 दिसंबर को डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 12th Fail ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। सिनेमाघरों की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी विक्रांत मैसी और मेधा शंकर की इस फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला है, जिसके चलते मेधा का नाम इस समय लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।

आईपीएस ऑफिसर की सच्ची कहानी है 12वीं फेल

27 अक्टूबर को रिलीज हुई 12वीं फेल, अनुराग पाठक के, इसी टाइटल वाले उपन्यास पर बेस्ड है। रियल लाइफ आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा और आईआरएस ऑफिसर श्रद्धा जोशी की इस कहानी को लोगों ने नॉवेल के रूप में भी खूब प्यार दिया था। फिल्म की कहानी दर्शकों को काफी पसंद आई है। ऑडियंस ने 12th फेल को साल 2023 की बेस्ट फिल्म का टैग दिया है। वहीं, आईएमडीबी पर इस मूवी को 10 में से 9.2 रेटिंग मिली है। इस फिल्म की सक्सेस के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में विक्रांत मैसी का कद और ऊंचा हो गया है।

नयनतारा के खिलाफ एफआईआर दर्ज

साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के लीड रोल वाली फिल्म अन्नपूर्णी को लेकर पिछले कुछ समय से काफी विवाद बना हुआ है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म में भगवान श्रीराम का अपमान करने और हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में वह फिल्म के निर्माता-निर्देशक और लीड एक्टर नयनतारा सहित पूरी टीम कानूनी पचड़ों में फंसी नजर आ रही है। जबलपुर में दर्ज हुई शिकायत हाल ही में खबर आई है कि फिल्म की पूरी टीम के खिलाफ मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक हिंदूवादी संगठन ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। उन्होंने टीम पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हिंदू सेवा परिषद के अतुल जेसवानी का कहना है कि फिल्म अन्नपूर्णी में कई ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं, जहां हिंदू धर्म के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का अपमान किया जा रहा है। फिल्म में कई जगहों पर भगवान श्रीराम के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां करते हुए हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है। अतुल के अनुसार, फिल्म में लव जिहाद को दिखाया गया है। इसके कलाकारों ने यह भी दिखाने की कोशिश की है वनवास के दौरान भगवान श्री राम जानवरों को मार कर मांस खाया करते थे।

9 जनवरी को दर्ज हुई FIR अब इस मामले में हिंदू सेवा परिषद् ने जबलपुर के थाना ओमती में 9 जनवरी, मंगलवार को फिल्म अन्नपूर्णी को हिंदू विरोधी बताते हुए निर्माता-निर्देशक और नयनतारा सहित फिल्म की स्टार कास्ट के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। सभी पर आईपीसी की धारा 153 और 34 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

अजब-गजब | इस गांव में होता है माइनस 71 डिग्री सेल्सियस तापमान

यहां ठंड के मारे हफ्ते में एक दिन नहाते हैं लोग

उत्तर भारत में ठंड सितम ढा रही है। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, यूपी-बिहार में भी कड़ाके की ठंड है, तापमान 5-6 डिग्री तक चला जा रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ठंडे गांव में कितना तापमान होता है? वहां का तापमान इतना कम है, कि भारत के लोगों को जब उसके बारे में पता चलेगा, तो शायद उन्हें गर्मी लगने लगे।

अगर आपको लग रहा है कि हम हवाई बातें कर रहे हैं तो चलिए आपको साइबेरिया के याकुत्सक गांव के बारे में बता देते हैं। फेसबुक पेज NSH Wonders पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक शख्स साइबेरिया के याकुत्सक गांव में है और नहाने की तैयारी कर रहा है। इतनी ठंडी जगह पर नहाना भी एक बड़ी प्रक्रिया की समान है। शख्स वीडियो में बताता है कि वो लोग हफ्ते में सिर्फ 1 दिन नहाते हैं। यहां का तापमान -71 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। नहाने से पहले पानी को गर्म करना पड़ता है। इस गांव में लोगों के पास पाइपलाइन नहीं है, क्योंकि पानी उसमें जम जाता है। इस वजह से लोग नहाने से पहले पानी गर्म करने के लिए बर्फ इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले वो पहले से स्टोर की हुई लकड़ियों को काटकर घर लाता है और आग जलाता है। जब आग अच्छे से जल जाती है तो वो बर्फ गर्म करने के लिए सबसे पहले बाहर जाता है

और बर्फ जमा करता है। बर्फ की सिल्ली के अलावा वो सड़क पर जमी बर्फ को भी जुटा लेता है। बर्फ पानी में बदल जाती है। बाथ हाउस के अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। वो बहुत गर्म होता है पर लोगों के लिए बहुत आराम देने वाला होता है। इस पूरी प्रक्रिया में 5 घंटे का वक्त लगता है।

इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक ने कहा कि यहां के लोग जरूर हफ्तेभर नहाने का इंतजार करते होंगे। एक ने कहा कि अगर ऐसा हो तो वो कभी न नहाए क्योंकि वो बहुत आलसी है। एक ने कहा कि उसे रोज नहाना अच्छा लगता है।

रोज हवाई जहाज से ऑफिस जाता है शख्स, 900 किलोमीटर का है सफर

ऑफिस जाने के लिए हर कर्मचारी अपने मुताबिक माध्यम का चयन करता है। कुछ लोग अपने वाहन से दफ्तर जाते हैं तो कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भरोसा करते हैं। कुछ लोग अपने लिए एक साथ महीने भर के लिए कैब या ऑटो भी लगा लेते हैं लेकिन आज तक शायद ही आपने सुना हो कि कोई रोजाना हवाई जहाज से ऑफिस जाता हो। चलिए आपको एक ऐसे पत्रकार से मिलवाते हैं, जो फ्लाइट पकड़कर दफ्तर पहुंचता है। आमतौर पर लोग दफ्तर जाने के लिए मेट्रो, ट्रेन या फिर कैब जैसे वाहनों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक रिपोर्टर चिप कटर ने ये बताकर लोगों को हैरान कर दिया कि वो ऑफिस जाने के लिए रोज़ फ्लाइट पकड़ते हैं। मजे की बात तो ये है कि इसकी वजह से उस पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ता बल्कि वो तो कहता है कि ये उसके लिए सस्ता पड़ जाता है। रिपोर्टर चिप कटर ने बताया कि न्यूयॉर्क में काम करने के लिए सप्ताह में तीन बार ओहियो से उड़ान भरता है। इसके लिए वो सुबह 6 बजे फ्लाइट पकड़ता है और उसे सुबह 4 बजकर 15 मिनट का अलार्म सेट करना पड़ता है। महामारी के दौरान वो घर से काम कर रहे थे और जब साल 2022 में उन्हें दफ्तर जाना हुआ तो उन्होंने न्यूयॉर्क में रुकने के बजाय ओहियो से न्यूयॉर्क फ्लाइट लेकर जाना शुरू कर दिया। दोनों शहरों के बीच दूरी 900 किलोमीटर की है और वो रोजाना ये सफर तय करते हैं। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ इससे प्रभावित हुई है लेकिन वे बताते हैं कि ये उन्हें न्यूयॉर्क में रहने से ज्यादा सस्ता है। चिप कटर ने इसके पीछे तर्क ये दिया है कि न्यूयॉर्क में अगर वो स्टूडियो फ्लैट लेकर रहता तो उसे हर महीने के लिए 3,200 यानि 2,65,581 रुपये देने पड़ते। ऐसे में उसके लिए फ्लाइट का सफर इससे सस्ता पड़ जाता है और उसकी सेविंग हो रही है। पहले वो मैनहट्टन में हाईएंड होटल में रुकता था, जो उसके ऑफिस के पास था लेकिन यहां उसके अच्छे पैसे खर्च हो रहे थे, जबकि उसका खाना-पीना भी प्रभावित होता था। आपको बता दें कि एक और टिकटॉक यूज़र सोफिया सेलेन्टानो ने भी बताया था कि वो प्लेन से सफर करके दफ्तर जाती हैं।

स्पीकर के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासी संग्राम

शिंदे शिवसेना ने कहा- फैसला सराहनीय, संजय राउत बोले- निर्णय एकतरफा शीर्ष अदालत जायेंगे

» नार्वेकर ने कहा- एकनाथ के नेतृत्व वाला शिवसेना का गुट ही असली राजनीतिक दल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मंबई। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि जून 2022 में प्रतिद्वंद्वी समूहों के उभरने पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना का गुट ही असली राजनीतिक दल था, जिसके कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री ने राज्य में शिवसैनिकों को बधाई दी।

इस फैसले के बाद राज्य की राजनीतिक घमासान शुय हो गया है। जहां भाजपा व शिवसेना गुट ने इसका स्वागत किया हे वहीं शिवसेना यूबीटी ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में जाएंगे।

किसी पार्टी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत : शिंदे

वहीं क्षेत्रीय भाषा में एक्स पर एकनाथ शिंदे की पोस्ट कहा गया- सबसे पहले, मैं राज्य के सभी शिवसैनिकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज एक बार फिर लोकतंत्र की जीत हुई है। राज्य के लाखों मतदाता जिन्होंने 2019 में शिवसेना-भाजपा गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दिया था, वे आज जीत गए हैं। यह शिव की जीत है। सैनिक, जो हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के विचारों के बैनर के साथ निकले थे। मुख्यमंत्री ने कहा, यह एक बार फिर साबित हो गया है कि हम बालासाहेब और धर्मवीर आनंद दिघे के हिंदुत्व विचारों के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। आज की जीत सत्य की जीत है। सत्यमेव जयते..। मुख्यमंत्री ने कहा आज का परिणाम किसी पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान और लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र में बहुमत हमेशा महत्वपूर्ण होता है। मूल पार्टी, शिवसेना को आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग और द्वारा हमें सौंप दिया गया है। तीर-कमान भी हमें थमा दिए गए हैं।

संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया : फडणवीस

देवेंद्र फडणवीस ने कहा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, राज्य में सरकार बनाते समय संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया। यही कारण है कि यह सरकार मजबूत और स्थिर है। हम शुरू से ही यह कहते रहे हैं। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि इस सरकार को बर्खास्त करने के लिए कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे मामला : आदित्य ठाकरे

सेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी स्पीकर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि शिवसेना प्रमुख के पास किसी भी नेता को पार्टी से निकालने की शक्ति नहीं है। उन्होंने इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि पार्टी प्रमुख की इच्छा और पार्टी की इच्छा पर्यायवाची हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को सौंपा गया 1999 का पार्टी संविधान मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए वैध संविधान था और ठाकरे समूह का यह तर्क कि 2018 के संशोधित संविधान पर भरोसा किया जाना चाहिए, स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने कहा, 1999 के संविधान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को सर्वोच्च निकाय बनाया।।

भाजपा नेता अन्नामलाई के खिलाफ मामला दर्ज

» धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने का है आरोप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई पर दो समूहों के बीच धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। धर्मपुरी पुलिस ने उनके खिलाफ बोम्मिड़ी पुलिस स्टेशन में धारा 153 (ए), 504, 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया। अन्नामलाई के खिलाफ ईसाई युवाओं के एक समूह के साथ हुए विवाद को लेकर मामले दर्ज किए गए थे, जिन्होंने 8 जनवरी को पप्पीरेड्डीपट्टी के पास बोम्मिडी में सेंट लूर्डेस चर्च के बाहर उनकी रैली एन मन एन मक्कल के दौरान चर्च में उनके प्रवेश पर आपत्ति जताई थी।

प्रदर्शनकारियों और भाजपा नेता के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिन्होंने उन्हें चर्च में प्रवेश करने से रोकने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया। इस शोर-शराबे का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। कुछ स्थानीय मीडिया पोर्टलों ने अपने एक्स

(पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर दृश्य पोस्ट किए। वीडियो में अन्नामलाई ने प्रदर्शनकारियों के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। इसके बाद, पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए युवाओं को वहां से हटाया, जबकि राज्य भाजपा अध्यक्ष को चर्च में प्रवेश करने और मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने की अनुमति दी।

निर्माण निगम के पूर्व एमडी सीपी सिंह के ठिकानों पर पड़ा छापा

» 1400 करोड़ रुपये के स्मारक घोटाले का है आरोप

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अंजाम दिए गए 1400 करोड़ रुपये के स्मारक घोटाले के आरोपी उप्र राजकीय निर्माण निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक सीपी सिंह के राजधानी स्थित तीन ठिकानों पर विजिलेंस ने छापा मारा। शासन के निर्देश पर विजिलेंस ने मंगलवार को सीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज करने के बाद यह कार्रवाई की है।

छापों में सीपी सिंह के दिल्ली, देहरादून, मुंबई, गुरुग्राम समेत कई अन्य शहरों में भी आलीशान प्रतिष्ठान, आवास आदि का भी पता चला है। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस की खुली जांच में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद विजिलेंस ने सीपी सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। इसकी मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को मुकदमा

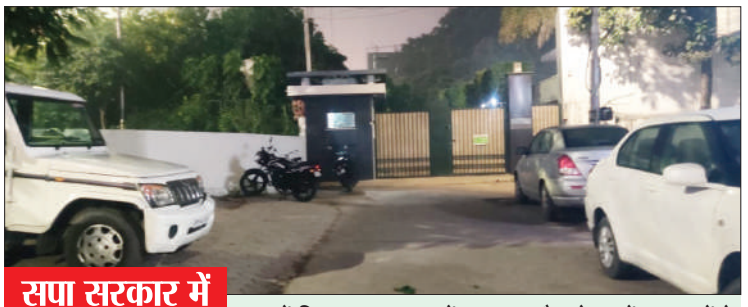

सपा सरकार में हुई विजिलेंस जांच

बता दें कि बसपा सरकार में लखनऊ और नोएडा में महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों और पार्कों के निर्माण में घोटाले की जांच वर्ष 2012 में सपा सरकार ने शुरू करायी थी। सपा सरकार ने पहले इसकी जांच लोकायुक्त संगठन से कराई, जिसने करीब 1400 करोड़ रुपये का घोटाला अंजाम देने की रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। तत्पश्चात राज्य सरकार ने इस मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी।

दर्ज करने के बाद सीपी सिंह के गोमतीनगर के विश्वास खंड, हजरतगंज के मदन मोहन मालवीय मार्ग और महानगर के ठिकानों पर विजिलेंस की टीमों ने छापा मारा। इस दौरान सीपी सिंह गोमतीनगर स्थित अपने आवास पर मौजूद मिले, जिसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया। जांच के दौरान उनके आवास पर जगुआर और बीएमडब्ल्यू जैसी बेशकीमती गाड़ियां और अन्य वस्तुएं बरामद की गयी हैं। साथ ही तमाम संपत्तियों के दस्तावेज, बैंक खाते और लॉकर्स का भी पता चला है। विजिलेंस बृहस्पतिवार को इन बैंक खातों को सीज कराने के साथ लॉकर्स को भी खुलवाने की कवायद करेगी।

राशिद की पीठ की सर्जरी, रिहैबिलिटेशन पर गए

» भारत के खिलाफ अफगान टीम से बाहर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मोहाली । अफगानिस्तान की टीम भारत के खिलाफ गुरुवार से यहां शुरू हो रही टी20 श्रृंखला में अपने 'ट्रंप कार्ड' राशिद खान के बिना ही खेलेगी लेकिन कप्तान इब्राहिम जदरान को टीम से अपने मजबूत प्रारूप में अच्छे प्रदर्शन उम्मीद है। वनडे विश्व कप के बाद नवंबर में राशिद ने पीठ की सर्जरी करायी थी, उन्हें टीम में शामिल किया गया था लेकिन वह 'रिहैबिलिटेशन' के कारण तीनों मैच में उपलब्ध नहीं हो पायेंगे।

जदरान ने कहा, ''वह पूरी तरह से फिट नहीं है। वह 'रिहैबिलिटेशन' कर रहा है। हमें श्रृंखला में उसकी कमी खलेगी। राशिद की अनुपस्थिति में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हमें भरोसा है। '' उन्होंने कहा, ''हमारे पास काफी खिलाड़ी हैं जैसे मुजीब जदरान जो काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है।

राशिद के बिना हमें परेशानी होगी लेकिन हमें किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। '' भारत में वनडे विश्व कप में अफगानिस्तान का प्रदर्शन सुर्खियों में रहा था। टीम लीग चरण में गत चैम्पियन इंग्लैंड और पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई थी।

इस सीरीज से टी-20 विश्व कप की तैयारियों में मदद मिलेगी: जदरान

इस श्रृंखला से अफगानिस्तान को टी20 विश्व कप की तैयारियों में मदद मिलेगी और उन्हें लगता है कि टीम को बल्लेबाजी विभाग में सुधार करना चाहिए। जदरान ने कहा, ''हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर मौजूद है, हमारे पास तेज गेंदबाज भी हैं लेकिन हमारा लक्ष्य बल्लेबाजी में सुधार करना है।'' वह टी20 विश्व कप से पहले अपना स्ट्राइक रेट भी सुधारना चाहते हैं। उनका 27 मैच में 103 का स्ट्राइक रेट है। जदरान के रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ पारी का आगाज करने की उम्मीद है। कप्तान ने कहा, ''मैं वनडे में टीम में 'एंकर' की भूमिका निभाता हूं। टी20 में मेरा लक्ष्य स्ट्राइक रेट में सुधार करने का है लेकिन यह भी हालात पर निर्भर करता है। जब टीम को जरूरत हो तो आपको भी आकर्षक शॉट खेलने में सक्षम होना चाहिए। मैं इस पर काम कर रहा हूं। अगर मैं अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा सकूं तो यह टीम के लिए अच्छा होगा।

शिक्षा के मामले में मुसलमानों की हालत एससी से भी नीचे : सिब्बल

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्पेशल स्टेट्स पर सुनवाई जारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के स्पेशल स्टेट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ताबड़तोड़ दलीलें दे रहे हैं। शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सिब्बल ने तर्क दिया कि देश में शिक्षा के मामले में मुसलमानों की हालत अनुसूचित जातियों (एससी) से भी नीचे है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं बनाया गया है।

हालांकि, सिब्बल के तर्क देने के दौरान सरकार की तरफ से दलील दे रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी पलटवार किया। वैसे जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान अक्सर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के दौरान नोकझोंक होती रहती थी। दोनों के बीच दलील रूपी आरोप-प्रत्यारोप जमकर चले। जब भी ये दोनों वकील आमने-सामने होते हैं, उनकी

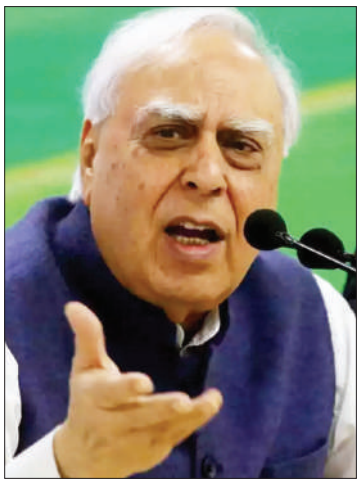

भिड़ंत रोचक होती है।

मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्पेशल स्टेट्स को लेकर चल रही सुनवाई का था। सिब्बल ने दलील दी कि अनुच्छेद 30 (अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार) में तो सिर्फ कुछ आरक्षण की बात है और अब उन्हें भी छीन लिया जाएगा! अगर हमारे प्रशासन में अनुचित दखल दिया गया तो निश्चित रूप से अदालतों का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

सरकार के रुख पर उठाए सवाल

यूपीए सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे सिब्बल ने सबसे पहले सरकार के रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले का समर्थन करने पर सरकार की आलोचना की, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र संसद द्वारा पारित कानून का समर्थन करने के लिए बाध्य है, और मोदी सरकार का रुख चिंताजनक है। सिब्बल 1981 में एएमयू अधिनियम में हुए संशोधन को फिर से लागू करने की दलील दे रहे थे। इस नियम में यह स्पष्ट किया गया था कि एएमयू, जो मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल (एमएओ) कॉलेज का नया रूप है, भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय है। इससे पहले, इसी प्रावधान में लिखा था विश्वविद्यालय से अर्थ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।

तो क्या सरकार आपातकाल के कुख्यात 39वें संविधान संशोधन का भी समर्थन करे : मेहता

सिब्बल की दलील के एक खामियों को उजागर करते हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि अगर सरकार को हर संसदीय कानून का समर्थन करना ही है, तो क्या उसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किए गए आपातकाल के कुख्यात 39वें संविधान संशोधन का भी समर्थन करना पड़ेगा? उस संशोधन ने तो मूलभूत अधिकारों को ही रोक दिया था। उन्होंने ये जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार का काम सिर्फ सही तरीके से कानून पेश करना है, न कि हर परिस्थिति में उसका बचाव करना। मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने 1981 के अधिनियम को सही ठहराया है और सरकार हमेशा हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करती है। मेहता ने तर्क देकर सिब्बल की दलील की धार को कुंद किया।

मणिपुर पावर स्टेशन से भारी ईंधन रिसाव कई जगह आग लगी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

» सरकार ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए

इंफाल। मणिपुर सरकार ने लीमाखोंग पावर स्टेशन से भारी ईंधन के रिसाव की सूचना के बाद सभी संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। ईंधन इंफाल घाटी से गुजरने वाली नदियों में फैल गया है। वीडियो फुटेज में अधिकारियों को रिसाव के बाद ईंधन से भरी धारा में एक छड़ी घुमाते हुए दिखाया गया है। कुछ स्थानों पर धारा में छोटी-मोटी आग लग गई।

सरकार ने एक आदेश में कहा लीमाखोंग पावर स्टेशन से भारी ईंधन के रिसाव की सूचना मिली है, जिसके कारण कांटोसाबल, सेकमाई आदि से गुजरने वाली धाराओं में डिस्चार्ज फैल गया है। यह धारा खुरखुल-लोइतांग-कामेंग-इरोइसेम्बा-नंबुल से होकर बहती हुई इम्फाल नदी से मिलती है। इसमें कहा गया है, सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध है कि वे मशीनरी, जनशक्ति और विशेषज्ञता के संदर्भ में सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके पर्यावरणीय आपदा को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें।

राज्य सरकार ने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया तंत्र और मानक संचालन प्रक्रियाओं को तुरंत सक्रि य किया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है, उपायुक्त (इंफाल पश्चिम) अगले निर्देश तक क्षेत्र में समन्वय करेंगे। मणिपुर के सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) मंत्री लीशांगथेम सुसींद्रो मेइतेई और वन मंत्री थोंगम विश्वजीत सिंह ने कल देर रात घटनास्थल का दौरा किया। यह घटना तब हुई है जब पिछले साल 3 मई को मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय झड़प के बाद मणिपुर में हिंसा की छिटपुट घटनाएं जारी हैं। हिंसा में अब तक 180 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।

अहमदाबाद और अयोध्या के बीच उड़ान शुरू

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। अहमदाबाद और अयोध्या को जोड़ने वाली पहली त्रि-साप्ताहिक उड़ान गुरुवार को शुरू की गई, जो राम मंदिर के बहुप्रतीक्षित अभिषेक समारोह से पहले नदी के किनारे स्थित यूपी शहर के विमानन बुनियादी ढांचे के विस्तार का प्रतीक है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वस्तुत: उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को चौथा अंतरराष्ट्रय हवाई अड्डा देने के लिए मैं पीएम मोदी का आभारी हूं।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी बस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

आगरा। उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण सर्दी के साथ-साथ घना कोहरा पड़ रहा है। कोहरे के कारण हर रोज सड़क हादसे हो रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग जान गंवा रहे हैं। अब बीती देर रात आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है।

यहां एक डबल डेकर बस खड़े ट्रक से टकराकर खाई में पलट गई, इस हादसे में बस में सवार 10 सवार लोग घायल हुए हैं, बताया जा रहा है कि दिल्ली से सवारियां लेकर बस लखनऊ की ओर जा रही थी। बस में करीब 40 सवारियां थीं। आशंका जताई जा रही है

40 लोग थे सवार बाल-बाल बची जान, 10 घायल

कि कोहरे के चलते बस हादसे का शिकार हुई है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू किया और घायल सवारियों को अस्पताल में भर्ती कराया।

मौके पर पहुंची पुलिस

पुलिस ने बताया कि आगरा के थाना डौकी क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 14 पर खड़े ट्रक से दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही डबल डेकर बस टकराकर एक्सप्रेसवे से नीचे खाई में पलट गइ। ये हादसा तब हुआ जब एक डबल डेकर बस खराब दृश्यता के कारण नियंत्रण खो बैठी और डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद कम से कम छह वाहन एक-दूसरे से टकराए।

गलन ने बढ़ा दी हाड़ कंपाने वाली ठंड

कोहरे की आगोश में प्रदेश, अभी और नीचे लुढ़केगा पारा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। लखनऊ गुरुवार की सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में घना कोहरा रहा। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। कोहरे के साथ गलन लोगों को परेशान करती रही। इसके पहले बुधवार को हल्की धूप जरुर निकली लेकिन हवाओं की वजह से गलन लोगों को ठिठुराती रही। पारे में उतार-चढ़ाव और हवा की चाल ठिठुरन बढ़ा रही है। बुधवार को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली पछुआ हवा ने गलन बढ़ा दी। इसके चलते धूप बेअसर रही।

हालांकि तापमान में विशेष बदलाव नहीं आया। अधिकतम तापमान 17 तो न्यूनतम 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक

अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, अगले दो-तीन दिन में अधिकतम तापमान दो डिग्री तक बढ़ने और न्यूनतम तापमान के लुढ़कने के आसार हैं।

फिलहाल गलन से राहत नहीं मिलेगी। ठंड को देखते हुए कक्षा आठ तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी व निजी स्कूलों में 13 जनवरी तक छुट्टी बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह अवकाश 6 से 10 जनवरी तक बढ़ाया गया था। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि नौवीं से 12वीं तक के सभी विद्यालय सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक चलेंगे। आदेश के मुताबिक विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य की ये जिम्मेदारी होगी कि कक्षा में ठंड से बचाव की व्यवस्थाएं कराएं। संभव हो तो कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से कराया जाए।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक - संजय शर्मा, विधि सलाहकार: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, वित्तीय सलाहकार: संदीप बंसल, कार्टूनिस्ट: हसन जैदी, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in
RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।